



एम. एन. आई. टी. के अठारहवें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्नातक व स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्रियाँ तथा स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में शिरकत की।

कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, ममता से और वार्ता की मांग

हड़ताली डॉक्टरों ने कहा कि पुलिस आयुक्त हटाने की मांग तो मान ली, स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों पर कार्यवाही बाकी है

उच्चतम न्यायालय के अनेक आग्रहों के बाद भी सरकारी अस्पतालों में 41 दिन से आउटडोर नहीं लग रहा है।

अनुरोध किया है अस्पतालों में धमकी की संस्कृति ने माहौल को खराब कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय और बर्नार्जी ने बार-बार डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया है। डॉक्टरों की हड़ताल से पिछले 41 दिनों से सरकारी अस्पतालों के रोगी विभागों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टरों फ्रंट

के तत्वावधान में मंगलवार रात डॉक्टरों ने एक आम सभा की और गत नौ अगस्त के आंदोलनकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला डॉक्टर ने दुष्कर्म और उसकी हत्या करने पर न्याय दिलावे, स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित कार्य संस्कृति बनाने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया।

मंगलवार को मनोज कुमार वर्मा के कार्यभार संभालने के साथ ही कोलकाता पुलिस प्रमुख को बदलने की हड़ताली डॉक्टरों की मुख्य मांग को पूरा कर दिया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की उनकी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर नाराजगी जताई।

गता 16 सितंबर को डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के साथ उनके कालीघाट स्थित आवास पर बैठक की जो पांच घंटे से अधिक समय तक चली। इससे पहले एसी दो बैठकें बिना किसी नतीजे के विफल रही।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

उल्लेखनीय है कि सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने की शुरुआत गत नौ अगस्त को हुई थी जब 31 वर्षीय द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर महिला डॉक्टर की आरजी कर मेडिकल और अस्पताल में दुष्कर्म और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा 14 अगस्त की रात को अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई तथा चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

‘यांत्रिक ज्ञान जरूरी है, परन्तु नैतिक और मानवीय मूल्य जुड़े रहें’

राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 में से 12 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिलने पर प्रसन्नता जताई

जयपुर, 18 सितम्बर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को एम.एन.आई.टी. के 18 वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश विश्व पर में अग्रणी बने। इसके लिए प्रौद्योगिकी संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करें। उन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को शोध अनुसंधान में मौलिक दृष्टि रखते हुए कार्य करने, पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने का आ आन किया। समारोह में 20 में से 12 स्वर्ण पदक छात्राओं को मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं तो देश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने संस्थान की फैकल्टी में एक तिहाई महिलाएँ होने को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रौद्योगिकी संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है, ताकि इनके जरिए भारत तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़े।

एमएनआईटी के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी शिरकत की और कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही ‘युवा नीति-2024’ लागेगी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने समारोह में 805 स्नातक, 477 स्नातकोत्तर, 79 पी.एच.डी. विद्यार्थियों को डिग्री दी तथा नए बने छात्रावास का लोकार्पण भी किया।

एम.एन.आई.टी. के निदेशक प्रो. एन.पी. पाढ़ी ने संस्था का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि संस्था को शोध व अनुसंधान में 15 पेटेंट मिल चुके हैं।

राष्ट्रपति ने समारोह में 805 स्नातक, 477 स्नातकोत्तर और 79 पीएचडी विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और 20 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने छात्रों के लिए निर्मित अरावली छात्रावास का लोकार्पण भी किया।

इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘विकसित भारत 2047’ की जो संकल्पना संजोई है, उसका मूल आधार यही है कि देश सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। इसमें

2024 तथा कौशल क्षमता विकास के लिए नई स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे युवाओं की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

शर्मा ने कहा कि युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने तथा उनमें उद्यमिता बढ़ाने के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को देश-विदेश के उत्कृष्ट सीईओ का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही, इसके तहत चयनित स्टार्टअप को 10 करोड़ रूपए तक की फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में एक हजार करोड़ रूपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर्स स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें।

एम.एन.आई.टी. के निदेशक प्रो. एन. पी. पाढ़ी ने संस्था का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संस्थान को शोध और अनुसंधान में 15 पेटेंट मिले हैं।

अरावली के पहाड़ पर खनन, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, 18 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोबनेर के मेहस्वांस गांव में अरावली पर्वतमाला में आने वाले गैर मुमकिन पहाड़ पर खनन को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख खान सचिव और खान निदेशक सहित अन्य से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार को खंडपीठ ने यह आदेश उम्मीद सेवा संस्थान की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिकवक्ता हेरन्ट नील ने अदालत को बताया कि जोबनेर के मेहस्वांस गांव में अरावली पर्वतमाला के अंग्रेजों गैर मुमकिन पहाड़ आता है। राज्य सरकार ने यहां खनन की अनुमति दी है। जबकि अरावली के अन्तर्गत आने

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोबनेर के मेहस्वांस गांव में अरावली पर्वतमाला में आने वाले गैर मुमकिन पहाड़ पर खनन के लिए मुख्य सचिव, प्रमुख खान सचिव आदि को नोटिस भेजा है।

के कारण यहां खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस गैर मुमकिन पहाड़ में गैर मुमकिन नदी का हिस्सा भी आता है। याचिका में आरोप लगाया गया कि खनन माफिया ने सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर पूरे 12.5 हेक्टेयर के पहाड़ का दोहन कर लिया है और अब यह समाप्त होने की करार पर है। खनन माफिया तय क्षेत्र से अतिरिक्त स्थान पर भी खनन कार्य कर रहा है। खनन के दौरान विस्फोटकों का भी उपयोग किया जाता है। याचिका में गुहार की गई है कि यहां खनन कार्य रोका जाए और खननकर्ताओं से भारी पेनल्टी वसूली जाए।

मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

क्लेम अपील में पिता-पुत्र की उम्र में मात्र 6 साल का अंतर

हाईकोर्ट ने इसे गंभीर मानकर प्रदेश के सभी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि क्लेम याचिका पेश होते ही दावेदारों और मृतक आदि के उम्र व जन्मतिथि से संबंधित आधार कार्ड के अतिरिक्त दुर्घटना से पूर्व का कोई एक दस्तावेज पेश करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो दावेदारों से इस संबंध में शपथ पत्र लें। यदि वांछित दस्तावेज पेश नहीं किए जाएं तो क्लेम याचिका को खारिज किया जा सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि लंबित क्लेम याचिकाओं में भी अधिकरण जरूरी समझे तो इस संबंध में निर्देश दे सकता है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश डूंगराम व अन्य की क्लेम याचिका को वापस लेने

के आधार पर खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि अधिक क्लेम राशि लेने के लिए दुर्घटना के बाद मृतक या घायल के दस्तावेजों में जानबूझकर उम्र कम लिखाई जाती है। ऐसे में आश्रितों की उम्र को समायोजित कर वास्तविकता से कम लिखते हैं। जिससे भ्रष्ट आचरण को प्रोत्साहन मिलता है। इस मामले में पिता-पुत्र में छह साल

का अंतर बताया गया है। ऐसे में सिर्फ छह साल की उम्र में पिता बना असंभव है। मामले के अनुसार एम.ए.सी.टी. कोर्ट संख्या 2 जयपुर द्वितीय, ने 7 अगस्त, 2020 को अपीलार्थी डूंगराम की पत्नी पार्वती देवी की दुर्घटना में मौत होने पर 7.71 लाख रूपए बीमा कंपनी को अदा करने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ डूंगराम व उसके पुत्रों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान अदालत की जानकारी में आया कि मृतक की उम्र 45 साल और उसके पति डूंगराम की आयु चालीस साल बताई गई है। जबकि वेद प्रदीप की उम्र 34 साल बताई गई। अदालत की ओर से उम्र संबंधी अनिश्चितता पकड़ने पर अपीलार्थी ने इस अपील को वापस लेने की अनुमति मांगी। इस पर अदालत ने अपील को खारिज करते हुए सभी दुर्घटना अधिकरणों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

“वन नेशन, एक इलैक्शन” ...

प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रबल सम्भावना रहेगी। लेकिन, इस समय इस मुद्दे को सामने लाकर, भाजपा यह सपना संजो रही है कि वह राजनैतिक माहौल को एक बार फिर से अपने पक्ष में कर लेगी।

भाजपा के थिंक टैंक के अनुसार, ओ.एन.ओ.ई. विपक्ष द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना की वकालत के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित हो सकता है। मोदी के पहले दो कार्यकालों की स्थिति के विपरीत, इस समय राष्ट्रीय राजनैतिक एजेंडा तैयार करने का काम एक प्रकार से विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। ओ.एन.ओ.ई. के सहारे, भाजपा राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाले ट्रेंड की जगह पर पुनः प्रतिष्ठित होना चाह रही है। लेकिन मूल चुनौती यह है कि ओ.एन.ओ.ई. भाजपा की ‘केन्द्रीयकृत अधिनायकवादी राजनीति’ के

खिलाफ विपक्ष के प्रचार-अभियान को और ज्यादा सशक्त बना देगा। विपक्षी नेताओं की ओर से कड़े विरोधी स्वरों की शुरुआत हो रही चुकी है। विपक्ष ओ.एन.ओ.ई. को भाजपा की एक ऐसी रणनीतिक रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीति पर एकल पार्टी प्रभुत्व स्थापित करना है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ओ.एन.ओ.ई. से संभवदा की भावना का अतिक्रमण होगा तथा यह नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को भी कमजोर कर देगा। अगर तथा जब कभी ओ.एन.ओ.ई. लागू होगा, कुछ राज्य सरकारों को, उन्हें संविधान-प्रदत्त पाँच साल के कार्यकाल का कुछ बाकी बचा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। यह सम्भव दिखाई नहीं देता कि इन राज्यों के मुख्यमंत्री, खासतौर से वहाँ विपक्ष की सरकार होने की स्थिति में, अपने कार्यकाल के बकाया हिस्से की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जायेंगे।

राहुल पर भाजपा नेताओं की टिप्पणी: कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी

नयी दिल्ली, 18 सितम्बर। कांग्रेस तथा उसके घटक संगठनों ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। कांग्रेस, भाजपा के नेताओं के बयान के खिलाफ सुबह से लामबद्ध है और पार्टी नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। एनएसयूआई ने इसके विरुद्ध मार्च किया और चारों भाजपा नेताओं का पुतला फूँका। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले चार नेताओं के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज की है।

नये कानूनों के तहत 5.5 लाख प्राथमिकी दर्ज हुई

नयी दिल्ली, 18 सितम्बर। देश में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद साढ़े पाँच लाख से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं और आठ लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने के मौके पर बताया कि, एक जूनवाँ को भारतीय न्याय संहिता लागू किये जाने के बाद से तीन सितंबर तक कुल 5.5 लाख हज़ार प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा नियमित प्रशिक्षण और वेबिनार के माध्यम से 8 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

केजरीवाल सभी सरकारी सुविधायें छोड़ेंगे

नयी दिल्ली, 18 सितंबर। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी सुविधाओं का त्याग करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए अनेकों काम किए। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी?

सिंह ने कहा कि दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं कि पिछले दो साल से भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के चूहे आरोप खड़े किए, जबकि एक

भारत-म्यांमार सीमा पर 31 हज़ार करोड़ रुपये की बाड़ लगेगी

नयी दिल्ली, 18 सितम्बर। मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए सरकार मैटैट तथा कुकी, दोनों समुदायों के साथ लगातार बात कर रही है और खुद केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में सुरक्षा स्थिति की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) को समाप्त कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पिछले सौ दिनों के दौरान मणिपुर में शांति बहाली एवं सुरक्षा के संबंध में अनेक विशेष कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 31 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से भारत-म्यांमार के बीच 1610 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और

सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त कर दी है।

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1610 किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की स्वीकृति दी है।

सीमा सड़कों के निर्माण के काम को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। मोरेह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगा दी गई है और मणिपुर में अन्यत्र 21 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है।

आतिशी ...

प्रथम पृष्ठ का शेष) जब केजरीवाल ने, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही, एक रणनीतिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल तथा मनीष सिसोदिया की निष्कलत्र सहयोगी रही आतिशी ने मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को वापस लाने का संकल्प लिया है। उन्हें 26-27 सितम्बर को आहूत होने वाले दिल्ली विधानसभा के सत्र में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना होगा। सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने के बाद, आतिशी ने दिल्ली के नागरिकों के हितों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने केजरीवाल को बचाव करते हुए, उन पर लगाये गए भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठा बताया तथा उन्हें अनुचित तरीके से निशाना बचाने के लिए केन्द्र सरकार की एजेंसियों की आलोचना की।